भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1929

30 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

मिथिला क्षेत्र में मखाने का विपणन

1929**. श्री गोपाल जी ठाकुर:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार के मिथिला क्षेत्र विशेषकर दरभंगा जिले में मखाने के प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दरभंगा जिले और बिहार में स्वीकृत परियोजनाओं, आवंटित धनराशि और उनकी वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का मिथिला क्षेत्र, विशेषकर दरभंगा में आधुनिक मखाना प्रसंस्करण इकाइयों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, पैकेजिंग केंद्रों और निर्यात-उन्मुख बुनियादी ढांचे की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो इसके स्थापित होने की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ग) : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) अपनी दो केंद्रीय योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), तथा एक केंद्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई(के माध्यम से मखाना प्रसंस्करण सहित संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं मांग-आधारित हैं और बिहार के दरभंगा जिले सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं।

स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायता अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, बिहार के दरभंगा, अररिया, कटिहार, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जिलों के लिए मखाना की ओडीओपी के रूप में पहचान की गई है। दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, बिहार में मखाना प्रसंस्करण के लिए 315 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए 12.77 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत है, जिनमें से, 2.71 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 97 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, दरभंगा जिले से हैं।

एमओएफ़पीआई स्वयं कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। हालाँकि, यह अपनी योजनाओं के माध्यम से मखाना प्रसंस्करण सहित ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। पीएमकेएसवाई के एक घटक, 'खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार(सीईएफ़पीपीसी(' योजना के अंतर्गत, बिहार के अररिया जिले में मखाना प्रसंस्करण से संबंधित एक परियोजना को 5 करोड़ रुपये की स्वीकृत सहायता अनुदान के साथ मंजूरी दी गई है।

*****